भारत के विद्युत क्षेत्र में भारी बदलाव

विशेष लेख

***अनुपमा ऐरी**

घरों तथा फैक्टरियों में सप्लाई के निरंतर अभाव और गुणवत्ता की कमी झेलते भारत के विद्युत क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में बड़ा बदलाव देखने क□ मिला है।

आज देश के लिए गर्व की बात है कि 3000-4000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली राज्यों क□ और वितरण कंपनियों क□ दिन के किसी भी समय रियल टाइम पर उपलब्ध है और पॉवर एक्सचेंज में बिजली रियायती दर पर उपलब्ध है।

पिछले तीन वर्षों में विद्युत क्षेत्र में म□दी सरकार द्वारा केन्द्रित सुधारों के कारण रियायती दर पर बिजली मिलने लगी है।

तीन वर्षों के अंदर भारत की कुल बिजली क्षमता लगभग एक तिहाही (31 प्रतिशत या 76,577 मेगावाट अतिरिक्त) बढ़ी है। बिजली क्षमता 2014 के 243 गीगावाट से बढ़कर मार्च 2017 में 320 गीगावाट ह□ गई और परम्परागत या क□यला आधारित बिजली क्षमता (ज□ देश की समग्र बिजली क्षमता का प्रमुख आधार है) बिजली क्षमता एक चौथाई यानी 26 प्रतिशत अर्थात् मार्च 2014 के 214 गीगावाट से बढ़कर मार्च 2017 में 270 गीगावाट ह□ गई।

वर्ष 2014 में ऊर्जा अभाव 42,428 मिलियन यूनिट (4.2 प्रतिशत) की थी, ज□ 2017 में कम ह□कर 7,459 मिलियन यूनिट (0.7 प्रतिशत) ह□ गयी। इसी तरह 2014 में शीर्ष ऊर्जा अभाव 6,103 मिलियन यूनिट (4.5 प्रतिशत) थी, ज□ 2017 में कम ह□कर 2,608 मिलियन यूनिट (1.6 प्रतिशत) रह गयी।

पिछले तीन वर्षों में यानी 2014-2017 में बिजली उत्पादन में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई (अस्थायी)। यदि उज्ज्वला जैसी ऊर्जा सक्षमता गतिविधियां नहीं चलाई गई ह□तीं, त□

बिजली उत्पादन में और वृद्धि हासी। 2014-16 में बिजली उत्पादन में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और यदि हम ऊर्जा सक्षमता गतिविधियों के कारण टाले गये उत्पादन क जाड़े त यह वृद्धि 9.5 प्रतिशत की हागी।

यह महत्वपूर्ण है कि भारत बिजली के कुल आयातक से बदलकर बिजली निर्यातक बन गया है और भारत ने 2017 में नेपाल-बांग्लादेश और म्यामांर क 5,798 मिलियन यूनिट बिजली का निर्यात किया।

विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन केवल विद्युत उत्पादन से नहीं हासा। बिजली ट्रांसमिशन क्षेत्र में भी उचित कदम उठाये गये। इसके परिणामस्वरूप पिछले तीन वर्षों में शानदार वृद्धि दिखी। सरकार के 'एक देश, एक मूल्य और एक ग्रिड' पहल के अनुरूप ट्रांसमिशन क्षेत्र में 36 प्रतिशत (एक तिहाई) की वृद्धि हुई। मार्च 2014 में ट्रांसमिशन क्षमता 5,30,546 एमवीए से बढ़कर मार्च 2017 में 7,22,949 एमवीए ह गई।

इसके साथ ही ट्रांसमिशन लाइनों में 26 प्रतिशत (एक चौथाई) की वृद्धि हुई। मार्च 2014 में ट्रांसमिशन लाइनें 2,91,336 सर्किट किलामीटर (सीकेएम) थी, ज बढ़कर मार्च 2017 में 3,66,634 सीकेएम ह गई। दक्षिण भारत क विकल्प अंतरण क्षमता में 87 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह क्षमता मार्च 2014 के 3,450 मेगावाट से बढ़कर मार्च 2017 में 6,450 ह गई।

देश के सभी गांवों में बिजली देने के मादी सरकार के कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में साथ-साथ किये गये सुधारों से भी विद्युत क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन संभव हुआ।

बिजली से वंचित गांवों क जाड़ने और ग्रामीण लागों की जिन्दगी में परिवर्तन लाने के लिए 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्याति याजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत ग्रामीण बिजलीकरण कार्यक्रम की घाषणा की गई। 2014 में बिजली से वंचित गांवों की संख्या 18,452 थी। सरकार के सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष फाक्रस के साथ चलाये गये इस कार्यक्रम से 12 मई, 2017 तक 18,441 गांवों में से 13,123 से अधिक गांवों में बिजली कनेक्शन प्रदान करके नई उपलब्धि हासिल की गई।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मादी ने लालकिले के प्राचीर से 15 अगस्त, 2015 क देश क संबाधित करते हुए यह वायदा किया था कि 1000 दिनों के अंदर शेष 18,452 गांवों (01 अप्रैल, 2015 तक) का बिजलीकरण कर दिया जाएगा। सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अंतर्गत मई 2018 तक सभी गांवों का बिजलीकरण कर दिया जाएगा, लेकिन गतिशील विद्युत, कायला, नवीकरणीय ऊर्जा तथा खान मंत्री श्री पीयूष गायल ने इस लक्ष्य की अवधि क कम कर दिया है और वह चाहते है कि दिसम्बर 2017 तक सभी गांवों का बिजलीकरण

ह जाए। यह अपने आप में कीर्तिमान हागा।

विद्युत क्षेत्र में सुधार की बात उज्ज्वला (सभी के लिए रियायती एलईडी से उन्नत ज्यति) की चर्चा किये बगैर अधूरी हागी।

ऊर्जा क्षमता अभियान के अंतर्गत सरकार की ओर से लगभग 23 कराड़ एलईडी बल्ब बांटे गये और निजी कंपनियों ने 33 कराड़ एलईडी बल्ब बांटे। इस कदम से उपभाक्ताओं के बिजली बिलों में प्रतिवर्ष 20,000 कराड़ रूपये की बचत हुई।

इस कार्यक्रम की सरकार की प्रमुख एजेंसी एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने केवल ऊर्जा सक्षम बल्ब ही नहीं बांटे, बल्कि पंखे, एयरकंडिशनर, ट्यूब लाइट (शहरी क्षेत्रों के लिए) और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए ऊर्जा सक्षम कृषि पंप भी बांटे।

भारत के विद्युत क्षेत्र के सुधार में सबसे बड़ा यागदान सरकार की उदय याजना (बिजली वितरण कंपनी आश्वासन याजना) का है। इस याजना से बिजली वितरण कंपनियों में बड़ा परिवर्तन हुआ है। बिजली वितरण कंपनियों क पहले बिजली क्षेत्र के सुधार की सम्पूर्ण कड़ी में सबसे कमजार कड़ी माना जाता था।

सरकार ने सतत बिजली वितरण कंपनियां विकसित करने के लिए उदय याजना लॉच की। तीन वर्षों के अंदर वित्तीय और संचालन परिवर्तन के लिए इस याजना में कुल 27 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश शामिल हुये हैं।

इस याजना से राज्य बिजली वितरण कंपनियों क लगभग 12,000 कराड़ रूपये की बचत हुई है। लगभग 85 प्रतिशत उदय बांड जारी किये जा चुके हैं (कुल 2.72 लाख कराड़ रूपये में से 2.32 लाख कराड़ रूपये)। परिणामस्वरूप बिजली वितरण कंपनियों के लिए ब्याज दरों में कमी हुई है।

सरकार के सुधार कार्यक्रमों के पीछे प्रेरक तत्व रही पारदर्शिता। अकेले बिजली क्षेत्र में विभिन्न माबाइल ऐप और वेबसाइट विद्युत मंत्रालय द्वारा लॉन्च किये गये, ताकि पारदर्शिता और दायित्व निश्चित किया जा सकें और उपभाक्ता विद्युत मंत्रालय के कामकाज और कार्य प्रदर्शन पर नजर रख सकें।

इनमें जीएआरवी (ग्रामीण बिजलीकरण) ऐप है, ज देश के गांवों और घरों में बिजलीकरण से संबंधित नवीनतम जानकारियां उपलब्ध कराता है। उज्ज्वला (एलईडी बल्ब) ऐप एलईडी वितरण के बारे में रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराता है। विद्युत प्रवाह (बिजली उपलब्धता और मूल्य) ऐप बिजली मूल्य और उपलब्धता के बारे में रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराता है। ऊर्जा (शहरी ज्यति अभियान) ऐप के माध्यम से उपभाक्ता

शहरों में बिजली वितरण कंपनियों के कार्य प्रदर्शन क□ देख सकते हैं। यह एकीकृत बिजली विकास य□जना (आईपीडीएस) के आंकड़े प्रदान करता है। तरंग (ट्रांसमिशन निगरानी प्रणाली) ऐप भारत में ट्रांसमिशन प्रणाली की प्रगति की देखरेख करता है। उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन य□जना (उदय) य□जना की प्रगति बताती है और बिजली वितरण कंपनियों की अतीत, वर्तमान तथा भविष्य की समस्याओं के स्थायी समाधान का आश्वासन देती है। ऊर्जा मित्र ऐप के माध्यम से नागरिक रियल टाइम आधार पर बिजली कटने की जानकारी ले सकते है।

पिछले तीन वर्षों में वास्तव में भारत ने विद्युत क्षेत्र में ऊंची छलांग लगाई है। सुधार कार्यक्रम और प्रक्रिया अबाध रूप से जारी है। इस क्षेत्र में हुये सुधारों की विश्व भर में चर्चा ह□ रही है। बिजली पहुंच संदर्भ में 2014 में विश्व में भारत का स्थान 99 था। अब भारत आगे बढ़ते हुए 26वें स्थान पर पहुंच गया है।

विद्युत मंत्री पीयूष ग□यल के शब्दों में यह कहना उचित ह□गा कि 'अनेक समस्याओं ने अनेक वर्षों तक भारत क□ पीछे रखा, लेकिन अब मूड बदल गया है'।

*लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं और ऊर्जा क्षेत्र पर नियमित रूप से लिखती हैं।

वीके/एजी/जीआरएस-76